

RBI ने रुपए में व्यापार नपिटान की अनुमति दी

प्रलम्बिस के लयि:

वदिश वयपार, मुदरा मूल्यहरास और अधमिल्यन, वैश्वकि अनुमोदन, भुगतान संतुलन

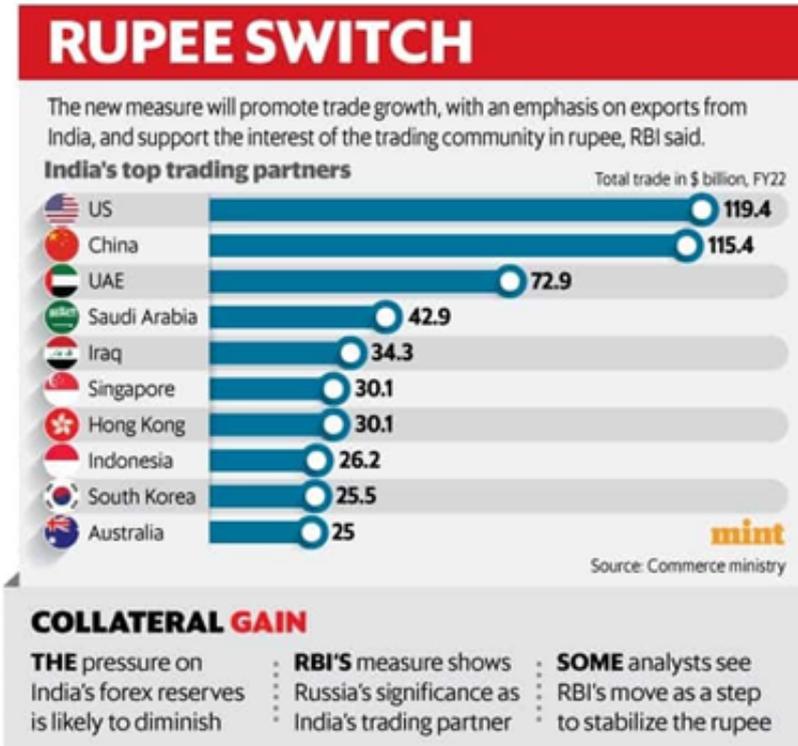
मेन्स के लयि:

भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्वकि अनुमोदनों का प्रभाव, रुपये में व्यापार को नपिटाने के लाभ और चुनौतियाँ, अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तकषेप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#) ने तत्काल प्रभाव से रुपए (INR) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुवधि के लयि एक तंत्र स्थापति कयि है ।

- हालाँकि ऐसे लेन-देन के लयि डीलर के रूप में कार्य करने वाले अधिकृत बैंकों को इसका उपयोग कर इसे सुवधिजनक बनाने के लयि नयामक से पूर्वानुमति लेनी होगी ।
- RBI द्वारा प्रस्तावति संशोधति फ़रेमवर्क के अनुसार, [वदिशी मुदरा प्रबंधन अधनियम \(FEMA\), 1999](#) के तहत कवर कयि गए क्रॉस-बॉर्डर नरियात और आयात को भारतीय रुपए में डनिॉमनिट और इनवॉइस कयि जा सकता है. हालाँकि RBI ने नरिधारति कयि है कदिनों व्यापार भागीदार देशों की मुदराओं के बीच वनिमिय दर बाज़ार के अनुसार नरिधारति की जाएगी



रुपया भुगतान तंत्र:

- भारत में अधिकृत डीलर बैंकों को रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी गई है (एक खाता जो एक अधिकृत बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है) ।

- इस तंत्र के माध्यम से आयात करने वाले भारतीय आयातक **भारतीय रुपए में भुगतान** करेंगे जो वदेशी वकिरेता से माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिये चालान भागीदार देश के अधिकृत बैंक के **वशिष वोस्ट्रो खाते** में जमा किया जाएगा।
- तंत्र का उपयोग करने वाले भारतीय नरियातकों को भागीदार देश के अधिकृत बैंक के नामति **वशिष वोस्ट्रो खाते** में जमा शेष राशि से भारतीय रुपए में नरियात का भुगतान किया जाएगा।
- भारतीय नरियातक उपर्युक्त **रुपए भुगतान तंत्र** के माध्यम से वदेशी आयातकों से भारतीय रुपए में नरियात के लिये अग्रमि भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
 - नरियात के लिये अग्रमि भुगतान की ऐसी किसी भी प्राप्ति की अनुमति देने से पहले भारतीय बैंकों को यह सुनिश्चिती करने की आवश्यकता है कि इन खातों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग पहले से ही नषिपादति नरियात आदेशों/पाइपलाइन में नरियात भुगतान से उत्पन्न भुगतान दायित्वों के लिये किया जाता है।
 - वशिष वोस्ट्रो अकाउंट में शेष राशि का उपयोग नमिनलखिति के लिये किया जा सकता है: परयोजनाओं और नविशों के लिये भुगतान, नरियात/आयात अग्रमि प्रवाह प्रबंधन, सरकारी प्रतभूतियों में नविश आदि।

मौजूदा तंत्र:

- यदि कोई कंपनी नरियात या आयात करती है, तो लेन-देन (**नेपाल और भूटान जैसे देशों को छोड़कर**) हमेशा एक वदेशी मुद्रा में होता है।
- इसलिये आयात के मामले में **भारतीय कंपनी को वदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है** (मुख्य रूप से डॉलर में और इसमें पाउंड, यूरो, येन आदि मुद्राएँ भी शामिल हो सकती हैं)।
- नरियात के मामले में भारतीय कंपनी को **वदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है** और कंपनी उस वदेशी मुद्रा को रुपए में परिवर्तित कर देती है क्योंकि उसे ज़्यादातर मामलों में अपनी ज़रूरतों के लिये रुपए की आवश्यकता होती है।

मौजूदा तंत्र के लाभ:

- विकास को बढ़ावा:
 - यह वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा और भारतीय रुपए के प्रति वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचिका समर्थन करेगा।
- स्वीकृत देशों के साथ व्यापार:
 - जब से रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, भुगतान की समस्या के कारण रूस के साथ व्यापार लगभग ठप है।
 - RBI द्वारा शुरू किये गए व्यापार सुविधा तंत्र के परिणामस्वरूप रूस के साथ भुगतान संबंधी मुद्दे को हल करना आसान हो गया है।
- वदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव:
 - इस कदम से **वदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव** का जोखिम भी कम होगा, वशिष रूप से यूरो-रुपया सममूल्यता को देखते हुए।
- रुपए की गरिवट पर नयितरण:
 - इस तंत्र का उद्देश्य रुपए में लगातार गरिवट के दौरान व्यापार प्रवाह हेतु रुपए में **नपिटान को बढ़ावा देकर वदेशी मुद्रा की मांग को कम करना है।**

अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत की पहल:

- रुपया-रूबल समझौता:
 - रुपया-रूबल व्यापार व्यवस्था डॉलर या यूरो के बजाय देय राशि का नपिटान रुपए में करने के लिये वैकल्पिक भुगतान तंत्र है।
 - रूस का स्टेट बैंक भारत में एक या एक से अधिक वाणजियिक बैंकों, जो कि वदेशी मुद्रा में व्यापार करने के लिये अधिकृत हैं, के साथ खातों का रखरखाव करेगा। इसके अलावा यदि बैंक आवश्यक समझता है तो भारतीय रज़िर्व बैंक के साथ स्टेट बैंक ऑफ रूस एक और खाता बनाए रखेगा।
 - भारत और रूस के नविसयियों द्वारा भुगतान को केवल उन्हीं नरिदषिट खातों में डेबिटि/क्रेडिट किया जाएगा।
- मुक्त व्यापार समझौता (FTA):
 - भारत ने हाल ही में **ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात** के साथ **मुक्त व्यापार समझौते** पर हस्ताक्षर किये हैं।
 - FTA दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और नरियात की बाधाओं को कम करने के लिये एक समझौता है।
 - मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार किया जा सकता है, जिसमें उनके वनिमिय को बाधति करने के लिये बहुत कम या कोई सरकारी शुल्क, कोटा, सब्सिडी या नषिध नहीं है।
 - मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद (Economic Isolationism) के विपरीत है।
- हदि-प्रशांत आर्थिक ढाँचा:
 - भारत एक **हदि-प्रशांत आर्थिक ढाँचा** (IPEF) स्थापति करने के लिये अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल में शामिल हो गया है, इस कदम से आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
 - सेवाओं के नरियात के लिये अमेरिका लगातार भारत का सबसे बड़ा बाज़ार रहा है, हाल ही में अमेरिका को सामान की बिक्री के मामले में भी इसने चीन को पीछे छोड़ दिया, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार बन गया।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. भुगतान संतुलन के संदर्भ में नमिनलखिति में से कौन चालू खाते का गठन करता है? (2014)

1. व्यापार संतुलन
2. वदेशी संपत्ति
3. अदृश्य का संतुलन
4. विशेष आहरण अधिकार

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 1, 2 और 4

उत्तर: C

व्याख्या:

- भुगतान संतुलन (BoP) में दो मुख्य पहलू- **चालू खाता और पूंजी खाता** शामिल होते हैं।
- BoP का चालू खाता माल, सेवाओं, नविश आय और हस्तांतरण भुगतानों के प्रवाह एवं बहरिवाह को मापता है। सेवाओं में व्यापार (अदृश्य), माल में व्यापार (दृश्यमान), वदेश से एकतरफा हस्तांतरण, प्रेषण तथा अंतरराष्ट्रीय सहायता चालू खाते के कुछ मुख्य घटक हैं। सभी वस्तुओं और सेवाओं का संयोजन एक देश के व्यापार संतुलन (BoT) को दर्शाता है। **अतः 1 और 3 सही हैं।**
- भुगतान संतुलन (Balance Of Payment-BoP) का अभिप्राय ऐसे सांख्यिकी विवरण से होता है, जो एक नश्चिती अवधि के दौरान किसी देश के निवासियों के विश्व के साथ हुए मौद्रिक लेन-देनों के लेखांकन को रिकॉर्ड करता है।
- नज्दी या सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा ऋण और उधार, नविश और वदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन पूंजी खाते के घटकों के कुछ उदाहरण हैं **अतः 2 और 4 सही नहीं हैं।**

अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rbi-allows-trade-settlements-in-rupee>